facts in our possession are concerned, there does not seem to be any material fact which will justify any change in the premium rates.

राज्यों को लोहा, सीमेंट आदि का अलाट किया जाना

*४९२. **श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया** : क्या **उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ के वर्षों में किन-किन राज्यों को कितना-कितना लोहा, सीमेंट तथा अन्य नियंत्रित सामग्री अलाट की गई सामग्री से अधिक मात्रा में दी गई और इसका क्या कारण था ?

† [ALLOTMENT OF IRON, CEMENT ETC. TO STATES

*492. SHRI V. M. CHORDIA: Will the Minister of INDUSTRY be pleased to state the names of the various States to which iron, cement afnd other controlled material was given in excess of the allotments made during the years 1960-61, 1961-62 and 1962-63 and the excess quantity given to each State, and the reasons therefor?]

उद्योग मंत्री (श्री एन० कानूनगो) : सीमेंट के अलावा अन्य कोई भी नियंत्रित सामग्री अलाट की गई मात्रा से अधिक मात्रा में नहीं दी गई जिसके बारे में अपेक्षित जानकारी देने वाला एक विवरण सदन की मेज पर रखा जाता है ।

विवरण

वर्ष १९६०–६१, १९६१–६२ और १९६२–६३ में अलाट की गई मात्रा से अधिक मात्रा में दी गई सीमेंट और ऐसा करने के कारण

राज्य	दी गई अधिक मात्रा (टनों में)			कारण
	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	
दिल्ली	८,५२१	–	–	दी गई अधिक मात्रा पिछले वर्ष दिये गये आर्डरों की थी ।
अण्डमान	८१४	–	–	
हिमाचल प्रदेश	३४७	–	–	
गुजरात	–	–	७,८६०	
उड़ीसा	–	–	१,१९२	
मणिपुर	–	–	८६८	
उत्तर प्रदेश	–	६,४२६	–	
आन्ध्र प्रदेश	९२,६००	३२,९६३	९,४२३	सरकार द्वार किये गये नियतन के अनुसार आन्ध्र, बिहार और मैसूर के सीमेंट कारखानों को सीमेंट भेजने के लिये नियमित रूप से कम वैगन मिलते रहे ।
बिहार	३३,९८३	–	८०८	
मैसूर	१८,७६०	२६,२८३	–	

†[ ] English translation.

राज्य	दी गई अधिक मात्रा (टनों में)			कारण †
	१९६०–६१	१९६१–६२	१९६२–६३	
				ये नियतन न केवल उन्हीं राज्यों में सीमेंट की खपत के लिये जिनमें कारखाने स्थित हैं, बल्कि आस-पास के तथा दूर के राज्यों द्वारा इस्तेमाल के लिये किये गये थे। वैगनों की कमी के कारण जहां कहीं सीमेंट राज्य के बाहर नहीं ले जाई जा सकी वहां अधिक मात्रा का इस्तेमाल उसी राज्य में कर लिया गया। विवश होकर सड़क से सीमेंट भेजी गई जिससे सम्बन्धित कारखानों में सीमेंट का उत्पादन अधिकतम हो सके।

ILTHE MINISTER OF INDUSTRY (SHRI N. KANUNGO) : No controlled material has been given in excess of the allotment excepting Cement, in respect of which a statement containing the required information is laid on the Table of the House.

†[ ] English translation.

STATEMENT

Excess despatches of Cement during the years 1960-61, 1961-62 *and* 1962-63 *together with the reasons therefor.*

State	Excess despatches (in tons)			Reasons
	1960-61	1961-62	1962-63	
Delhi	8,521	..	..	The excess despatches were against the orders placed in the previous year.
Andamans	814	..	..	
Himachal Pradesh	347	..	..	
Gujarat	..	..	7,860	
Orissa	..	..	1,192	
Manipur	..	..	868	
Uttar Pradesh	..	6,426	..	
Andhra	92,600	32,963	9,423	Cement factories in Andhra, Bihar and Mysore have regularly been getting short supplies of wagons for movement of cement, in accordance with allocations made by Government. Such allocations were for consumption of cement, not only in these States where factories are situated but also to neighbouring and distant States. Wherever, on account of short supply of wagons cement could not be moved outside the State, the excess supply had to be consumed within the State, resorting to movement by road with a view to keeping the production of cement in the factories concerned at maximum level.]
Bihar	33,983	..	808	
Mysore	18,760	26,283	..	

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान को यह ज्ञात है कि मध्य प्रदेश को १९६०-६१ में २५,१९७ मैट्रिक टन, १९६१-६२ में १९,०१३ मैट्रिक टन और १९६२-६३ में १६,५३५ मैट्रिक टन जितना अलाट किया गया था उससे कम दिया गया जब कि दूसरे प्रान्तों को जितना अलाट किया गया उससे अधिक दिया गया ? ऐसा भेदभाव करने का मुख्य कारण क्या है ?

श्री एन० कानूनगो : वह आंकड़े तो हमें याद नहीं रहे ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : आपकी किताब में से पड़ा है, आपको याद रहना चाहिये ।

श्री एन० कानूनगो : लेकिन चीज यह है कि सीमेंट की कमी है और विभिन्न प्रदेशों को जो मांग है उसको पूरी तरह से पूरा नहीं किया जा सकता है जैसे कि १९६०-६१ में दिल्ली की २०१ हजार टन की मांग थी लेकिन उन्हें एलाट किया गया १४० हजार टन । इसलिये हर एक स्टेट की जो मांग है उसमें बहुत कमती दिया जाता है और जो दिया जाता है बहुत सी स्टेट्स उसको भी पूरा नहीं उठाती हैं । मध्य प्रदेश के बारे में मैं यह कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश को १९६०-६१ में २१८ हजार टन एलाट हुआ था और उसमें से उन्होंने २१० हजार टन उठाया, १९६१-६२ में २०७ हजार टन एलाट हुआ था और उसमें से उन्होंने २०० हजार टन उठाया और १९६२-६३ में १९४ हजार टन एलाट हुआ था और उसमें से उन्होंने १७९ हजार टन उठाया ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : क्या श्रीमान् यह स्पष्ट बतायेंगे कि एलाटमेंट हो जाने के पश्चात् मध्य प्रदेश सरकार की गल्ती की वजह से जो एलाटेड सीमेंट थी वह नहीं ली गई अथवा एलाटेड सीमेंट को आपने उनको उपलब्ध नहीं कराया इसलिये नहीं ली ?

श्री एन० कानूनगो : एलाटेड सीमेंट उपलब्ध होने में भी दिक्कत रहती है, मैं नहीं कह सकता कि कैसे हुआ और क्या हुआ ।

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : स्पष्ट उत्तर आना चाहिये ।

MR. CHAIRMAN: He has said that he does not know whether it is due to their fault or his fault.

श्री विमलकुमार मन्नालालजी चौरड़िया : अब श्रीमान ने प्रश्न के उत्तर में बताया कि जो एलाट करते हैं वह भी नहीं उठाते हैं लेकिन यह जो स्टेटमेंट दिया है उसमें यह बताया है कि कुछ प्रान्तों को जो एलाटेड सीमेंट था उससे काफी अधिक मात्रा में सीमेंट दिया गया जैसे कि आन्ध्र प्रदेश को ९२,६०० टन, बिहार को ३३,९८३ टन और मैसूर को १८,७६० टन अधिक सीमेंट दिया गया जब कि मध्य प्रदेश को जो एलाटेड सीमेंट था उतना भी नहीं दिया गया, तो ऐसा भविष्य में न हो इसके लिये शासन ने क्या प्रबन्ध किया है ?

श्री एन० कानूनगो : अधिक देने का एक कारण यह हुआ कि रेलवे कैपेसिटी नहीं थी, मान लीजिये कि बिहार और आन्ध्र प्रदेश में जो सीमेंट बनी उसको उठाने के लिये रेलवे की कैपेसिटी नहीं मिली इसीलिये वह लारी से भेजा गया और लारी से नजदीक भेजा जा सकता है, लारी से दूर नहीं भेजा जा सकता है तो जब तक कि रेलवे कैपेसिटी पूरी न मिले तब तक सीमेंट की मूवमेंट में ये दिक्कतें रहेंगी ।

SHRI R. S. KHANDEKAR: The hon. Minister said that the allotment to Madhya Pradesh could not be made according to the demand. May I know what is the reason for giving excess amount, more than their demand, in regard to other States? From the statement it is evident that various States have been given more than their due. What is the reason?

SHRI N. KANTJNGO: I have stated that because of difficulty of transport the allotment had to be made.

SHRI SITARAM JAIPURIA: The Minister of Industry says that railway wagons are not available for the

transport of cement, etc. and the Railway Minister always claims that railway wagons are available in plenty. I would like to know from the how. Minister as to which of the two statements is correct.

MR. CHAIRMAN: Both in their way.

SHARAVATHY PROJECT

•493. SHRI A. D. MANI: Will the Minister of IRRIGATION AND POWER be pleased to state:

(a) whether Government have received any report from the Government of Mysore regarding the allegations made by the Opposition in *ihe* Mysore Vidhan Sabha of irregularities in the working of the Sharavathy Project; and

(b) whether Government have conducted any enquiries into these allegations, and if so, with what result?

THE MINISTER OF IRRIGATION AND POWER (DR. K. L. RAO): (a) and (b) Attention of Government has been drawn to certain alleged irregularities in Sharavathy Valley project. The allegations have been looked into and there is no -*prima facie* case for detailed enquiry.

SHRI A. D. MANI; Is it a fact that the hon. Minister visited the project in October, 1963, stayed there for a few hours and gave a clean bill of health to the project? On wha'; basis did Government come to the conclusion that there was no substance in the various allegations made by Members of the Opposition in the Mysore Legislative Assembly?

DR. K. L. RAO: Before proceeding to the site the allegations were before me and "they were studied very carefully for more than a month. The visit was really taken not for making further enquiries so much as for seeing the progress of the work which was already getting behind schedule. Therefore, it is not correct to say that the observations made at the time were the result of a few hours' stay.

SHRI A. D. MANI; is it a fact that over Rs. 60 lakhs have been paid to contractors as compensation on purely technical grounds and the Opposition in the Mysore Assembly has alleged that there is corruption involved in this transaction?

DR. K. L. RAO: I would request the hon. Member to go through the White Paper issued on the 2nd March 1964 by the Government of Mysore in this connection. Broadly speaking I may state that the allegation in respect of payment to contractors was as a result of the award given by the arbitrator. Under certain clauses of the contract, arbitration can be resorted to. The contractors resorted to arbitration and the award was given. The Government took great pains to negotiate after the award was given and in some cases they have reduces the amount. For example, for a contractor of the Talakalle dam Rs. 198 lakhs was given as an award and it was settled for about Rs. 14 lakhs.

SHRI A. D. MANI: Has the attention of the Minister been drawn to a statement made by the Chief Minister of Mysore on the floor of the Legislative Assembly that there was need for a judicial enquiry? This statement was made before the White Paper wag Since so many allegations have been made, what is there to prevent a judicial enquiry from being ordered into the allegations?

DR. K. L. RAO: The fact that the Chief Minister of Mysore thought that a White Paper was much better than a judicial enquiry is itself the answer to the question. I may also tell the hon. Member that the Chief Minister must have done it—I do not know and T have not seen that particular answer by the Chief Minister—due to too many questions being asked and the hot atmosphere prevailing at the moment.